INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता संवर्धन से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों का वर्णनात्मक मूल्यांकन

डॉ. अखिलेश कुमार सेन

सहायक प्राध्यापक, विभाग: राजनीति विज्ञान , भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

सार

यह अध्ययन छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता संवर्धन के लिए संचालित सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं का तुलनात्मक-वर्णनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह शोध-पत्र राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28, बिहान योजना, महतारी वंदन योजना, महतारी शक्ति ऋण योजना, स्वसहायता समूह कार्यक्रमों, माइक्रोफाइनेंस सुविधाओं और कौशल विकास प्रशिक्षण योजनाओं की संरचना, उद्देश्यों, वित्तीय प्रावधानों और परिणामों का विश्लेषण करता है। द्वितीयक आँकड़ों, सरकारी प्रकाशनों, नीति दस्तावेज़ों और अकादमिक शोध-पत्रों के आधार पर यह अध्ययन उजागर करता है कि कैसे ये नीतियाँ ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, उनकी आजीविका में सुधार लाने, और समाज में उनकी भूमिका को मजबूत करने में योगदान दे रही हैं। वर्ष 2024-25 में स्वसहायता समूहों के माध्यम से 561 करोड़ रुपये का प्रावधान और 2.29 लाख महिला समूहों की स्थापना इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

मुख्य शब्द: ग्रामीण महिला उद्यमिता, नीति विश्लेषण, स्वसहायता समूह, माइक्रोफाइनेंस, कौशल विकास, सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, योजना मूल्यांकन

1. प्रस्तावना

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमिता एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक बन गई है। छत्तीसगढ़ राज्य–जो देश के कृषि-प्रधान क्षेत्रों में से एक है–ने पिछले दशक में महिला उद्यमिता संवर्धन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति दर्शाई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2023-24 के अनुसार, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 41.7 प्रतिशत हो गई है, और ग्रामीण भारत में यह वृद्धि सबसे तीव्र रही है (भारत सरकार, 2024)।

राज्य सरकार ने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए एक बहु-स्तरीय नीति ढाँचा विकसित किया है। ये नीतियाँ (1) वित्तीय सहायता, (2) कौशल विकास, (3) सामूहिक संगठन, (4) प्रशिक्षण एवं परामर्श, (5) बाजार संपर्क, और (6) सामाजिक सुरक्षा के आयामों को व्यापक रूप से कवर करती हैं (छत्तीसगढ़ शासन, 2024)। यह अध्ययन इन समस्त नीतियों और कार्यक्रमों का एक समन्वित विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

2. राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय नीति ढाँचा

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

2.1 छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28

छत्तीसगढ़ राज्य ने 2023 में एक समर्पित महिला उद्यमिता नीति को अपनाया, जो भारत में अपनी तरह की प्रथम सुनिश्चित नीति है। इस नीति के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं (छत्तीसगढ़ शासन, 2023):

1. **विनिर्माण उद्यम परियोजनाएँ:** महिला उद्यमियों को अधिकतम ₹50,00,000 का ऋण सहायता
2. **सेवा उद्यम परियोजनाएँ:** अधिकतम ₹25,00,000 की वित्तीय सहायता
3. **व्यवसाय उद्यम परियोजनाएँ:** अधिकतम ₹10,00,000 तक का समर्थन
4. **कार्यशील पूँजी सहायता:** 45-70 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान
5. **मार्जिन मनी:** नए उद्यमों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम ₹75 लाख तक
6. **स्वसहायता समूहों के लिए विशेष प्रावधान:** अतिरिक्त 5 प्रतिशत अनुदान
7. **स्टार्टअप को अतिरिक्त प्रोत्साहन:** 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान और 1 वर्ष की अतिरिक्त समय-सीमा

इस नीति की संरचना उद्यमों के आकार और प्रकृति के आधार पर भिन्न-भिन्न स्तरों के समर्थन प्रदान करती है, जिससे विविध उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, 2024)।

2.2 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और बिहान कार्यक्रम

दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का क्रियान्वयन समस्त ग्रामीण महिला उद्यमिता संवर्धन का केंद्रीय स्तंभ है। छत्तीसगढ़ में इसे "बिहान" नाम से संचालित किया जाता है (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2024):

- **स्वसहायता समूह (एसएचजी) का निर्माण:** 2.29 लाख महिला समूहों की स्थापना
- **चक्रिय निधि:** ₹344.77 करोड़ का प्रावधान
- **सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ):** 1.35 लाख समूहों को ₹1,045.47 करोड़ की सहायता
- **बैंक लिंकेज:** प्रत्येक समूह को ऋण तक सरल पहुँच
- **2024-25 बजटीय आवंटन:** महिला रोजगार सृजन के लिए ₹561 करोड़
- **कृषि सखी कार्यक्रम:** 4.62 करोड़ महिला किसानों को जैविक और टिकाऊ कृषि प्रशिक्षण

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

बिहान कार्यक्रम की विशेषता यह है कि यह स्वसहायता समूहों के नेटवर्क को सशक्त सामुदायिक संस्थानों में रूपांतरित करता है, जो आजीविका विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं (छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, 2024)।

2.3 महतारी वंदन योजना और महतारी शक्ति ऋण योजना

छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 2024 में महतारी वंदन योजना को अपनाया, जो राज्य की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करती है (महिला एवं बाल विकास विभाग, 2024):

महतारी वंदन योजना की संरचना:

- **मासिक सहायता:** ₹1,000 प्रति माह
- **लाभार्थी:** 70 लाख महिलाएँ (वर्ष 2024-25 तक)
- **वितरण विधि:** सीधा लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) बैंक खातों में
- **उद्देश्य:** स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण

इसके अनुक्रम में, महतारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की गई, जो महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है (सामाजिक कल्याण विभाग, 2024):

तालिका 1: महतारी शक्ति ऋण योजना: मुख्य विनिर्देश

ऋण सीमा	ब्याज दर	पुनर्भुगतान अवधि
₹10,000 - ₹25,000	0% (प्रारंभिक 3 माह)	36 माह
लाभार्थी पात्रता	महतारी वंदन योजना सदस्य	17.5 लाख महिलाएँ

3. स्वसहायता समूह कार्यक्रम और सामूहिक संगठन

3.1 एसएचजी की संरचना और कार्यप्रणाली

स्वसहायता समूह छत्तीसगढ़ की महिला उद्यमिता की रीढ़ हैं। प्रत्येक समूह में 10-20 सदस्य होते हैं, जो सामाजिक पूँजी और आर्थिक सहायता का एक दोहरा नेटवर्क बनाते हैं (भारतीय रिज़र्व बैंक, 2024):

1. **सामाजिक पहलू:** सदस्यों के बीच विश्वास, सहयोग और सामूहिक निर्णय

2. **आर्थिक पहलू:** बचत, ऋण, और साझा निवेश
3. **प्रशिक्षण:** वित्तीय साक्षरता, व्यवसाय प्रबंधन, और कौशल विकास
4. **बैंक संपर्क:** प्रत्यक्ष ऋण सुविधाओं तक पहुँच
5. **बाजार संपर्क:** सामूहिक विपणन और उत्पाद बिक्री के अवसर

3.2 प्रशिक्षण और क्षमता विकास

बिहान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, 2024):

तालिका 2: बिहान योजना: प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

प्रशिक्षण प्रकार	अवधि	प्रतिभागी
वित्तीय साक्षरता	5 दिन	समूह नेतृत्व
कौशल विकास (आजीविका)	3-6 माह	15-35 आयु वर्ग
व्यवसाय प्रबंधन	10 दिन	उद्यमी महिलाएँ
जैविक कृषि (कृषि सखी)	वर्ष भर	किसान महिलाएँ
डिजिटल साक्षरता	2 माह	सभी सदस्य

4. माइक्रोफाइनेंस नीतियाँ और वित्तीय समावेशन

4.1 माइक्रोफाइनेंस संस्थानों की भूमिका

छत्तीसगढ़ में माइक्रोफाइनेंस की संरचना तीन स्तरों पर कार्य करती है (नीति आयोग, 2024):

1. **प्राथमिक स्तर:** स्वसहायता समूह (आंतरिक बचत और ऋण)
2. **द्वितीयक स्तर:** समूह संघ और बैंक-लिंक्ड कार्यक्रम
3. **तृतीयक स्तर:** बैंकिंग प्रणाली और विशेषीकृत वित्तीय संस्थान (नाबार्ड, आरबीआई निर्देश)

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

4.2 ऋण वितरण और पुनर्भुगतान

2024-25 में राज्य के आँकड़े निम्नलिखित हैं (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 2023):

- **ऋण वितरण:** 220 स्वसहायता समूहों को ₹2.69 करोड़ का ऋण
- **औसत ऋण आकार:** ₹1,22,272 प्रति समूह
- **पुनर्भुगतान दर:** 92-95 प्रतिशत (औसत)
- **ब्याज दरें:** 8-12 प्रतिशत (ब्याज अनुदान के साथ 2-4 प्रतिशत प्रभावी दर)
- **गारंटी सहायता:** सूक्ष्म उद्योग विकास कोष (एमयूडीएफ) से 85 प्रतिशत तक

4.3 वित्तीय समावेशन के संकेतक

ई-श्रम पोर्टल पर छत्तीसगढ़ की पंजीकरण संख्या (दृष्टि आईएएस, 2023):

तालिका 3: वित्तीय समावेशन के संकेतक (2024-25)

श्रेणी	पंजीकृत संख्या
कुल महिला कार्मिक (ई-श्रम)	16.69 करोड़ (राष्ट्रीय)
असंगठित क्षेत्र कार्मिक	42.74 करोड़ (राष्ट्रीय)
औपचारिक क्षेत्र (ईपीएफओ) महिलाएँ	1.56 करोड़ (7 वर्षों में जोड़ी गईं)

5. नीति कार्यान्वयन, चुनौतियाँ और प्रभाव मूल्यांकन

5.1 नीतियों के सकारात्मक प्रभाव

अनुसंधान-पत्रों और सरकारी रिपोर्टों से प्राप्त साक्ष्य निम्नलिखित सकारात्मक परिणाम दर्शाते हैं (अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ रिव्यूज़ एंड रिसर्च इन सोशल साइंसेज़, 2024):

1. **आय सृजन:** बिहान योजना से जुड़ी महिलाओं की औसत मासिक आय ₹4,000-₹7,000 बढ़ी है
2. **रोजगार सृजन:** 2021-2023 के बीच महिला-नेतृत्व वाली एमएसएमई से 89 लाख अतिरिक्त रोजगार

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

3. **आत्मनिर्भरता:** स्वसहायता समूहों की 78 प्रतिशत महिलाएँ अब आत्मनिर्भर हैं
4. **परिवारिक निर्णय:** 82 प्रतिशत महिलाओं को परिवारिक वित्तीय निर्णयों में भूमिका मिली
5. **शिक्षा और कौशल:** 65 प्रतिशत महिलाओं ने कम से कम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया है

5.2 संरचनात्मक चुनौतियाँ

नीतियों के कार्यान्वयन में अनेक बाधाएँ विद्यमान हैं (विश्व बैंक, 2024):

1. **विकेंद्रीकरण की कमी:** दूरदराज के गाँवों तक समान सेवाएँ नहीं पहुँचतीं
2. **प्रशिक्षण की अपर्याप्त गुणवत्ता:** सीमित प्रशिक्षकों और संसाधनों के कारण
3. **बाजार संपर्क की कमजोरी:** महिलाओं को उत्पाद विपणन में कठिनाई
4. **डिजिटल विभाजन:** 40 प्रतिशत महिलाएँ अभी भी डिजिटल साक्षरता से वंचित हैं
5. **पारिवारिक दबाव:** सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड महिलाओं के उद्यमिता प्रयासों में बाधा डालते हैं
6. **भूमि स्वामित्व की समस्या:** केवल 13.88 प्रतिशत महिलाओं के पास कृषि भूमि है

5.3 नीति समन्वय और अंतराल विश्लेषण

विभिन्न नीतियों के बीच समन्वय की कमी एक महत्वपूर्ण अंतराल है (छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग, 2024):

तालिका 4: नीति समन्वय विश्लेषण

नीति	मुख्य लक्ष्य	समन्वय अंतराल
महिला उद्यमिता नीति	उद्यम स्थापना	कौशल विकास से जुड़ाव कमजोर
बिहान (एनआरएलएम)	आजीविका विकास	बाजार संपर्क और उत्पाद विपणन अपर्याप्त
महतारी वंदन	आय सहायता	स्वरोजगार के साथ एकीकरण सीमित
कौशल विकास	प्रशिक्षण	नियोक्ता संपर्क और नियुक्ति सहायता कमजोर

6. तुलनात्मक नीति मूल्यांकन

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

6.1 राष्ट्रीय बनाम राज्य नीतियों की तुलना

1. **राष्ट्रीय नीतियाँ (एनआरएलएम):** व्यापक, लचीली, और सामूहिक संगठन पर केंद्रित
2. **राज्य नीतियाँ:** महिला-केंद्रित, अधिक आक्रामक समर्थन, और परिवार-आधारित मूल्य पर जोर
3. **दक्षता:** राज्य नीतियाँ बेहतर पहचान और लक्ष्य पहुँच प्रदान करती हैं
4. **पहुँच:** राष्ट्रीय नीतियों की व्यापक नेटवर्क संरचना है, परंतु राज्य नीतियाँ अधिक व्यक्तिगत हैं

6.2 वित्तीय सहायता की तीव्रता तुलना

तालिका 5: नीतियों का वित्तीय तुलनात्मक विश्लेषण

योजना	प्रधान लाभ	अधिकतम राशि	2024-25 आवंटन
महिला उद्यमिता नीति	विनिर्माण ऋण	₹50 लाख	₹250 करोड़ (अनुमानित)
बिहान (एनआरएलएम)	स्वसहायता समूह	₹5-10 लाख/समूह	₹561 करोड़
महतारी वंदन + शक्ति	मासिक + ऋण	₹1,000 + ₹25,000	₹840 करोड़ (वार्षिक)
दीनदयाल उपाध्याय कौशल	कौशल प्रशिक्षण	₹1.5-2 लाख (स्टाइपेंड सहित)	₹120 करोड़

7. सिफारिशें और भविष्य की दिशा

7.1 नीति सुधार के सुझाव

1. **डिजिटल एकीकरण:** सभी नीतियों में डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन विपणन और ई-कॉमर्स को अनिवार्य करना
2. **बाजार संपर्क केंद्र:** प्रत्येक ब्लॉक में महिला-संचालित बाजार संपर्क केंद्र स्थापित करना
3. **भूमि सुधार:** महिलाओं के लिए कृषि भूमि की सहसुविधा और संयुक्त स्वामित्व को प्रोत्साहित करना

4. **नीति समन्वय:** सभी नीतियों को "महिला आजीविका मिशन" के अंतर्गत एकीकृत करना
5. **पुरस्कार प्रणाली:** उच्च प्रदर्शन करने वाली महिलाओं और समूहों के लिए प्रोत्साहन राशि
6. **सामाजिक संरक्षण:** बीमा योजनाओं को सभी नीतियों के साथ जोड़ना
7. **युवा महिला केंद्र:** 18-25 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष हब
8. **अंतर-समूह नेटवर्क:** समूहों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान प्रणाली

7.2 भविष्य के लिए राहें

2025-2030 के दौरान छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिला उद्यमिता को निम्नलिखित पथ पर अग्रसर होना चाहिए:

- **अधिकार-आधारित दृष्टिकोण:** महिलाओं को लाभार्थी नहीं बल्कि अधिकार-धारी के रूप में स्वीकार करना
- **पर्यावरण-सचेत उद्यमिता:** जैविक, स्थानीय और पर्यावरण-अनुकूल व्यवसायों को बढ़ावा
- **सामाजिक उद्यम:** महिला-नेतृत्व वाली सहकारिता और सामाजिक व्यवसायों को समर्थन
- **अंतर-पीढ़ीगत संपर्क:** माता-बेटियों को संयुक्त प्रशिक्षण और उद्यमिता कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना

8. निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ राज्य में महिला उद्यमिता संवर्धन के लिए अपनाई गई नीतियाँ और कार्यक्रम काफी व्यापक और संरचनात्मक हैं। राज्य महिला उद्यमिता नीति २०२३-२८, महतारी वंदन योजना, महतारी शक्ति ऋण योजना, स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम और माइक्रोफाइनेंस सेवाएँ मिलकर एक समग्र ढाँचा बनाती हैं। हालाँकि, इन नीतियों का सफल कार्यान्वयन अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ग्रामीण अंचल में बैंकिंग सेवाओं की कमी, सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ, शैक्षणिक अक्षमता और बाजार तक पहुँच की समस्याएँ प्रमुख अवरोध बनी हुई हैं। फिर भी, उपलब्ध शोध साक्ष्य से पता चलता है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण संभव है। महिलाओं ने व्यवहारिक रूप से सिद्ध किया है कि सही समर्थन, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के साथ वे न केवल आत्मनिर्भर हो सकती हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सरकार को इन नीतियों के कार्यान्वयन में और अधिक सुधार करना होगा, स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने होंगे, बाजार सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी, और महिलाओं के साथ नियमित संवाद स्थापित रखना होगा। इसके अलावा, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से परिवार और समाज की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी आवश्यक है। यदि ये सभी पहलुएँ सही तरीके

से लागू किए जाएँ, तो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता का विकास न केवल संभव है, बल्कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है।

संदर्भ

1. अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ रिव्यूज़ एंड रिसर्च इन सोशल साइंसेज़. (2024). *भारतीय ग्रामीण विकास में स्व-सहायता समूहों की भूमिका.* https://ijrrssonline.in/
2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार. (2024). *दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: कार्यक्रम दिशा-निर्देश.* https://www.pib.gov.in/
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान). (2024). *बिहान कार्यक्रम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24.* https://bihan.gov.in/
4. छत्तीसगढ़ शासन, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय. (2024). *आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ 2024-25.* https://descg.gov.in/Economic-Survey.aspx
5. छत्तीसगढ़ शासन, औद्योगिक विभाग. (2023). *छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28.* https://cghidjp.cgstate.gov.in/
6. छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग. (2024). *ग्रामीण महिला आजीविका एवं उद्यमिता कार्यक्रमों पर राज्य रिपोर्ट.* https://dprcg.gov.in/
7. दृष्टि आईएएस. (2023). *छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28: विश्लेषण.* https://www.drishtiias.com/hindi/
8. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत. (2023). *राज्य वित्तीय एवं सामाजिक क्षेत्र अवलोकन: छत्तीसगढ़.* https://cag.gov.in/
9. नीति आयोग, भारत सरकार. (2024). *ग्रामीण महिला उद्यमिता: नीति विश्लेषण एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन.* https://niti.gov.in/
10. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़. (2024). *स्वसहायता समूह संचालन एवं मार्गदर्शन दस्तावेज़.* https://prd.cg.gov.in/
11. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय. (2024). *आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25: अध्याय–श्रम एवं रोजगार.* https://www.indiabudget.gov.in/budget2024-25/economicsurvey/
12. भारतीय रिज़र्व बैंक. (2024). *सूक्ष्म वित्त संस्थान नीति एवं दिशा-निर्देश.*

https://www.rbi.org.in/

13. महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़. (2024). *महतारी वंदन योजना: कार्यान्वयन मार्गदर्शिका.* https://cgwcd.gov.in/
14. विश्व बैंक. (2024). *ग्रामीण महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण पर भारत आधारित अध्ययन.* https://www.worldbank.org/hi/news/feature/2024/11/21/giving-a-boost-to-rural-women-entrepreneurs
15. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार. (2024). *ई-श्रम पोर्टल: असंगठित क्षेत्र श्रमिक सांख्यिकी.* https://www.eshram.gov.in/
16. सामाजिक कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़. (2024). *महतारी शक्ति ऋण योजना: योजना विवरण.* https://mahtarivandan.cgstate.gov.in/